



This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 23 फरवरी, 2011/4 फाल्गुन, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd January, 2011

No. HHC/GAZ/14-278/2004.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 16 days earned leave w.e.f. 27.12.2010 to 11.1.2011 with permission to prefix gazetted holiday and Sunday fell on 25th and 26th December, 2010 respectively in favour of Shri Basant Lal Verma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Rampur Bushahr, H.P.

Certified that Shri Basant Lal Verma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.



HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd January, 2011

No.HHC/GAZ/14-312/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 8 days earned leave w.e.f. 7.1.2011 to 14.1.2011 in favour of Shri Amardeep Singh, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(IV), Mandi, H.P.

Certified that Shri Amardeep Singh has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Amardeep Singh would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(IV), Mandi, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/-Registrar General

योजना विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग)

अधिसूचना

शिमला, 31 जनवरी, 2011

संख्याःपी०एल०जी०-ए(4)-5/2009(डीडी).—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, उप निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, उप निदेशक, वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2011 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. निरसन और व्यावृत्तियां.— (1) अधिसूचना संख्याः 9–28/71–योजना (स्थापना) तारीख 26–8–1991 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, उप निदेशक, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियमों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप—नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, अजय त्यागी, प्रधान सचिव (योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार। उपाबन्ध-'क

के लिए भर्ती और हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में उप निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद प्रोन्ति नियम।

- 1. पद का नाम.---उप निदेशक
- 2. पदों की संख्या.—02 (दो)
- 3. वर्गीकरण.—वर्ग—I (राजपत्रित) ।
- लिए वेतनमान/पै वेतनमानः (विस्तृत रूप में अंकित दरे).—(i) नियमित पदधारियों के 15600-39100 रु० पै बैन्ड+6600रु० ग्रेड पे।
- (ii) संविदा पद नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलक्षियां: स्तम्म संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरें अनुसार 22,200 /-
- 5. चयन पद अथवा अचयन पद.---चयन
- 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—45 वर्ष और इस से कम :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुन्नेय हैं :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार कि रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों रिवायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की स्रेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए है/किए गए थे।

- (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद(पदों) को आवेदन आमत्रित करने के लिए, यथारिथति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
- (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों कि दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
- सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-अनिवार्य अर्हताः

174

अर्थशास्त्र / 18 सांख्यिकी ជ सांख्यिकी 4 जिज्य / गणित में स्नातकोतर डिग्री या इसके समतुल्य। विश्वविद्यालय मान्यता

न

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय संस्थान से दो वर्ष का स्नातकोतर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।
- सांख्यिकी में अनुसंधान में लगमग तीन वर्ष का अनुभव या सांख्यिकीय डाटा एकत्रण, विश्लेषण तथा विवेचन किया हो।

(ख) वांछनीय अर्हता :

- हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं (ख) हिमाचल प्रदेश के में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए, प्रोन्नत व्यक्तियों की –आयु : लागू नहीं । दशा में लागू होंगी या नहीं.-

शैक्षिक अर्हता :लागू नहीं ।

- -दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—
- पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशातता.—शत-प्रतिशत प्रोन्नेति द्वारा, ऐसा न होने पर सेकैडमेंट आधार पर, दोनों के न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्म संख्या 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तथाकथित स्तम्म में विनिर्दिष्ट सेवा शतौं द्वारा विनियमित होंगे।
- 11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रीणयां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,** स्थानान्तरण किया जाएगा.—सांख्यिकीयविद/जिला सांख्यिकीय अधिकारी और अनुसन्धान अधिकारी/ सांख्यिकीय अधिकारी में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार पर, हिमाचल तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमेंट द्वारा:

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम वे कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से न कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—I:—— उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल' से, साधारणत: तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी। स्पष्टीकरण—I:-

स्पष्टीकरण-II:---उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

- जिला लाहौल एवं स्पिति।
- वम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
 - 3
- रोहडू उप मण्डल का डोडरा–क्वार क्षेत्र। जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट । 4
- कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 5
- कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 6
 - जिला किन्नौर। 7
- सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत, रेणुकाजी तहसील 8
- के भलाड़—भलौना तथा सांगना पटवार वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।
 मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल—बगड़ा पटवार वृत, बालीचौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगढ़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह—भडवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार वृत, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच—बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।
- अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्मरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी: (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्मरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर उपर्युक्त आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उनसे वरिष्ट सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ट व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे। स्पष्टीकरणः—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मंड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान—टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबंधों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाम दिए गए हों या जिसे एक्स—सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्मरक पद पर ातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदः नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

- द्वारा सरकार 1 संरचना.-हो तो उसकी यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान नय-समय पर गिठत की जाए।
- में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया -जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो। करने जार्या-
- 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- **15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यकम आदि, यथारिथति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धनों और शतौं के अध्यक्षीन की जाएगी :-

उप-निदेशक को, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर (1) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी बढा या जा सकेगा : परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

- -प्रधान सचिव, अर्थ एवं सांख्यिकी, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा। खि) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:–
- चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शतौं के अनुसार किया जाएगा ।
- (ii) संविदात्मक उपलब्धियां:—संविदा आधार पर नियुक्त उप—निदेशक को 22,200/—रु० की समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/ वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 670/—रु० (पद के पे बैन्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।
- नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—प्रधान सचिव, (अर्थ एवं सांख्यिकी) हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
- (iv) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यकम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- हिमाचल -जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् (v) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति. लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
- -अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध –ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा। (vi) करार.-

9044

- (vii) निबन्धन और शर्ते.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 22,200/-रु० की नियत पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 670/- पद के पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेंड पे का तीन प्रतिशत की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे विरिष्ट/ वियन क्विदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा वेतनमान आदि नही दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आवरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आविश्मक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और ऍल0टी०सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी । केंबल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । को किसी भी प्रकार का अन्य
- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा में अनधिकृत अनुपर्स्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (डयूटी) से अनुपर्स्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच साल का कार्यकाल पूर्ण कर आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना लिया है, आव अपेक्षित हो। (d)
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्मवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त अस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्मवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते भत्ते का हकदार होगा। (B)
- नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर—एस.आर., साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्म में यथावर्णित उपलक्षियों आदि के लिए हकदार होंगे। आदि संविदा पर निधि नियम, पैंशन नियम, साधारण भविष्य <u></u>
- **16. आरक्षण.—**सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों∕अनुसूचित जनजातियों∕अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।
- -सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय परीक्षा.-
- समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की शिथिल करने की शिवत.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबंध—"ख"

हिमाचल प्रदेश (वित/अर्थ एवं सांख्यिकी) सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप। मध्य प्रधान सचिव उप निदेशक और हिमाचल प्रदेश सरकार के

	सावदा पर ानयुक्त व्याक्त (।जस इसम ज्यपाल के मध्य	"द्वितीय पक्षकार" कहा गया	
पुत्र/पुत्री श्री	ानवास। इसके पश्चात " प्रथम पक्षकार " कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य.	नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात "द्वितीय पक्षकार" कहा गया	को किया गया।
यह करार श्री/श्रीमति	निवासी इसके पश्चात " प्रथम पक्षकार " कह	्रिक्स माहि	है) के माध्यम से आज तारीख

का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी 'द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने

को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को,दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना और....... को समाप्त हान वाल 19न (1977, 547 नन नन) नाम है और दोनों पक्षकारों सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों(पद का नाम) के रूप में नोटिस आवश्यक नही होगाः यह कि प्रथम पक्षकार अर्थात

यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/ विस्तारित परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष किया जाएगा।

- प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 22,200/— रु० प्रतिमास होगी । ri
- प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्व कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित ;समाप्तद्ध किए जाने के लिए दायी होगी। 3
- संविदा पर नियुक्त (पद का नाम), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित(पद का नाम) को, किसी भी प्रकार नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० इत्यादि का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्य के लिए भी हकदार नही होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त..... 4
- नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्तकर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा। 5
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो। 6
- चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्टीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव 7



- होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
 - 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी / कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।
 - 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को, कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई०पी०एफ० / जी०पी०एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्तााक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों 1.	की उपस्थिति में:	
2.	(नाम व पूरा पता)	
	(नाम व पूरा पता)	(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
साक्षियों 1.	की उपस्थिति में	
2.	(नाम व पूरा पता)	
	(नाम व पूरा पता)	(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

Authoritative English text of this Department _otification _o. PLG-A(4)5/2009(DD)Dated 31.01.2011 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India.

PLANNING DEPARTMENT (Economics & Statistics)

NOTIFICATION

Shimla, 31st January, 2011

No. PLG-A(4)5/2009(DD).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Director, (Class-I Gazetted) in the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification; namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Economics and Statistics Department, Deputy Director (Class-I Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2011.



- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, machal Pradesh.
- 2. Repeal and Savings.—(1) The Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Director (Class-I Gazetted), in the Economics and Statistics Department notified vide Notification No.9-28/71-Plan(Estt.), dated the 26th August, 1991, are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
AJAY TYAGI.
Principal Secretary(Plg., Eco. &Stat.).

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (GAZETTED) CLASS-I, IN THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS, HIMACHAL PRADESH

- Name of the Post.—DEPUTY DIRECTOR
- 2. Number of Posts: 02 (Two)
- 3. Classification : Class I (Gazetted)
- Scale of Pay: i) Pay scale for regular incumbent:
 Pay Band 15600-39100 + 6600 Grade Pay.
 ii) Emoluments for Contract employees
 - 22, 200/- as per details given in Col. No.15-A.
- 5. Whether Selection Post or Non-Selection Post.—Selection
- 6. Age for direct recruitment.—45 years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his ad-hoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies



shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

- (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
- (2) Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
- 7. Minimum educational & other qualifications required for direct recruits.—(1) ESSENTIAL QUALIFICATION: i) Master's degree in Statistics or in Economics/ Commerce/ Mathematics (with statistics) of recognized University or equivalent.

OR

A degree from a recognized University followed by two years post graduate training in a recognized Statistical Institute.

- ii) About 3 years experience in research in Statistics or in collection, analysis and interpretation of statistical data.
- b) **DESIRABLE QUALIFICATION(S):** Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
- 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s) .—Age: Not applicable. Educational Qualification: Not applicable.
- **9. Period of probation, if any.**—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- 10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of Post(s) to be filled in by various methods.—"100 % by promotion failing which by second basis, failing both by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column".
- 11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—"By promotion from amongst the Statisticians/District Statistical officer and Research officer/Statistical Officer with five years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by secondment from amongst the officers holding equivalent posts under the Centre/State Government.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those eployees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at-least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

- District Lahaul & spiti.
- 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
- 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
- 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District shimla.
- 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
- District Kinnaur.
- Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Siormour District.
- 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, GadaGussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kothog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
- (1) In all cases of promotion, the continuous *ad-hoc* service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the *ad-hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules.

Provided that where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;



- **EXPLANATION.**—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rules 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.
- (2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *adhoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the *ad-hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad-hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

- 12. If the departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
- 13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
- 14. Essential requirement for a direct recruitment/contract appointment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
- 15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *Viva-Voce* test, if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.
- 15(A) (Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
- (I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Deputy Directort in Department of Economics & Statistics, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year- to- year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

- (b) **POST FALLS WITHI_ THE PURVIEW OF HP PSC.**—The Pr. Secretary(Eco.& Stat.) to the Govt. of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in the Rules.
- (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Deputy Director appointed on contract basis will be paid consolidated contractual amount @ 22,200/- P.M. (which shall be equal to

minimum of pay band +Grade Pay). An amount of 670/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

- (III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (Eco. & Stat.) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.
- (IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
- (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Public Service Commission.
- (VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
- (VII) TERMS & CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ 22,200/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount 670/- (3% of the minimum of the pay band + Grade pay of the post) for further extended years respectively and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. shall be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/ she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and L.T.C. etc. Only Maternity leave will be given as per rules.
- (d) Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (e) An officer appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular officials at the minimum of pay scale.



- (h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & enduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
- 16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Schedule Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
- 17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
- 18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission to relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE-B

Form of contract /agreement to be executed between the Deputy Director and the Government of Himachal Pradesh through Principal Secretary (Eco.& Stat.) to the Govt. of Himachal Pradesh.

of in the year S/oD/oShri
_contract appointee (hereinafter
(Designation of
the SECOND PARTY). Whereas, the and the FIRST PARTY has agreed to
ntract basis on the following terms &
ervice of the SECOND PARTY as a iod of 1 year commencing on day It is specifically mentioned contract of the FIRST PARTY with ted on the last working day i.e. onnecessary.
contract period of HOD shall issue a e contract appointee was satisfactory ract is to be renewed/extended.
1

- 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be 22,200 /- per month.
- 3. The services of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/contract of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

- Contractual (Name of the post) will be entitled for one day casual leave 4. after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual (Name of the post). He/she will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
 - 5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual (Name of the post) will not be entitled for salary for the period of absence from duty.
 - 6. An officer appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
 - Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a 7. Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
 - Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officer/ official.
 - The Employees Group Insurance Scheme as well as E.P.F./G.P.F. will not be 9. applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:	
(Name and Full Address)	(Signature of the FIRST PARTY)
2	(Signature of the PIKST PAKTT)
(Name and Full Address)	
IN THE PRESENCE OF WITNESS:	
(Name and Full Address)	(Signature of the SECOND PARTY)
(Name and Full Address)	